

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 जून 2023 — ज्येष्ठ 17, शक 1945

गृह विभाग, सी-अनुभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2023

आदेश

क्रमांक एफ 04-75/गृह-सी/2023. — यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 15 मई, 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने के कारण “शिक्षा सत्र चालू होने से एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथा कृषि कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के सीमांकन/बंटाकन/नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु किया जाना आवश्यक होने जैसे महत्वपूर्ण कार्य एवं पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों के कार्य भी प्रभावित होने” से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची क-क के खंड (सात) “विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं” में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में, राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा, कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 03 माह के लिए प्रभावी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ प्रसाद कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 7th June 2023

ORDER

No. F 04-75/Home-C/2023. — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in essential service relating to "students are facing difficulty in obtaining caste, residence, income certificates, with the commencement of the education session and recruitment to vacant posts being under process, and before the commencement of the agriculture work, the demarcation / distribution / renaming of agricultural land in rural areas is necessary for the benefit of government schemes, such as important work and in the absence of Patwari report, the work of revenue courts is being affected", due to the indefinite strike by the Patwaris of the Revenue Department in the State from May 15, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits the refusal to work, by the patwaris of the Revenue Department, in the essential service specified in sub-clause (vii) of clause AA of Schedule "the services under the Head of the Departments and their subordinate office" which will be effective for the next 03 months from the date of issue of the order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DASHRATH PRASAD KOUSHAL, Deputy Secretary.